Date - 31 Jan 2022

शून्य अभियान

- सदियों पहले भारत ने इस दुनिया को एक अनोखा तोहफा दिया था जो शून्य था। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट की इस खोज ने संपूर्ण ज्ञान को एक नई दिशा दी-विज्ञान और तकनीकी खोजों ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया।
- इससे प्रेरणा लेते हुए अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग और कुछ अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से 'जीरो कैंपेन' शुरू किया था और अब 25 जनवरी को इन संगठनों ने इस अभियान पर आधारित एक ब्रांड फिल्म रिलीज की है|
- ईंधन की खपत और उपयोग के कारण देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर ध्यान दिया जा रहा है.
- इसे बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने पिछले साल एक 'जीरो' अभियान शुरू किया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस अभियान का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को शून्य पर लाना है।
- 15 सितंबर, 2021 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया के सहयोग से एक 'जीरो' अभियान शुरू किया।
- इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और लोगों को शून्य प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में जागरूक करना है।
- यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को ऐसी कंपनियों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जो शहरों में माल ढुलाई के काम में लगी हुई हैं.
- इनमें ई-कॉमर्स कंपनियां, फ्लीट एग्रीगेटर, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और माल ढुलाई में लगी कंपनियां शामिल हैं। इनमें ओला, उबर और जोमैटो जैसी कंपनियां शामिल हैं।

'जीरो' अभियान के तीन चरण हैं –

- पहले चरण के तहत कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की जाएगी; दूसरे के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा; और तीसरे चरण के तहत लोगों को ऑनलाइन टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी।

Yojna IAS

- जिससे वे अपने लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों की गणना करने में सक्षम होंगे और साथ ही 'जीरो' अभियान के अब तक क्या लाभ हैं, इस तीसरे घटक के तहत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कॉर्पोरेट ब्रांडिंग चरण में-

- इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के वाहनों पर 'जीरो' कैंपेन का लोगो होगा और उस ड्राइवर को भी ऐसा ही बैज मिलेगा.
- इससे इन कंपनियों की विश्वसनीयता और ब्रांडिंग बढ़ेगी और उन्हें और अधिक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- दूसरे घटक में-
- लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाएगा और साथ ही बताया जाएगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में माल ढुलाई से होने वाले कुल CO2 उत्सर्जन में केवल शहरी मालवाहक वाहन ही 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक यह उत्सर्जन बढ़कर 114 प्रतिशत हो सकता है।

दूसरे चरण में-

- लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाएगा और साथ ही बताया जाएगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में माल ढुलाई से होने वाले कुल CO2 उत्सर्जन में केवल शहरी मालवाहक वाहन ही 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक यह उत्सर्जन बढ़कर 114 प्रतिशत हो सकता है।

तीसरे चरण में-

- टूलकिट का अर्थ है कि आप किसी इलेक्ट्रिक वाहन के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या अन्य प्रकार के वाहनों का उपयोग करके यह गणना करने में सक्षम होंगे कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान विभिन्न साइटों पर उपलब्ध समान खरीद सकते हैं, उत्पाद की कीमतों की तुलना करें।

- बढ़ता शहरीकरण ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा रहा है; वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है; ईंधन के लिए अन्य देशों पर भारत जैसे देश की निर्भरता और बैटरी प्रौद्योगिकी में हालिया सुधार, ये सभी कारक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की जरूरत है।
- लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सभी अभी भी इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन पर इस समय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह बहुत गंभीरता

से काम करने की आवश्यकता है। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बहुत कम है और जो भी हैं वह बंद पड़े हैं।

- इसके अलावा आज की दौड़ को देखते हुए कंपनियों को ऐसी बैटरियां बनानी पड़ती हैं जिनकी रेंज ज्यादा हो यानी उनका माइलेज ज्यादा हो। साथ ही इन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करना भी जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें खरीद सकें।
- भारत के पास घरेलू उत्पादन के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसी सामग्रियों का कोई ज्ञात भंडार नहीं है, जबकि ये चीजें बैटरी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- आज भारत लिथियम आयन बैटरी के आयात के लिए जापान और चीन जैसे देशों पर निर्भर है। यानी हमें बैटरी के क्षेत्र में और अधिक शोध करने की जरूरत है।
- इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत के लिए कुशल श्रमिकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना, फेम योजना, परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना आदि।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल

- भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर एक रक्षा निर्यातक देश की छवि बनाने का फैसला किया है। अब तक भारत को हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत फिलीपींस की नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा।
- ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के लिए भारत आने वाला यह पहला विदेशी ऑर्डर है।

- फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के साथ **$375** मिलियन **(2,812** करोड़ रुपये**)** के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डील फिलीपींस के क्यूजॉन सिटी में नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट में आयोजित होने वाले एक इवेंट में की गई।
- अतुल डी राणे, सीईओ, ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंडिया, संजीव जोशी, डिप्टी सीईओ, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नेगी और प्रवीण पाठक इस अवसर पर उपस्थित थे।
- गौरतलब है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से तीन गुना यानी **4321** किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने में सक्षम है।
- यह रक्षा सौदा चीन के लिए सही नहीं माना जाता है।
- दरअसल, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का चीन के साथ विवाद है। फिलीपीन मरीन का इरादा ब्रह्मोस का उपयोग तट-आधारित एंटी-शिप मिसाइल के रूप में करना है। दक्षिण चीन सागर उन संभावित क्षेत्रों में से एक है जहां इस प्रणाली को तैनात किया जा सकता है।
- इस सौदे में तीन बैटरियों की डिलीवरी, ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण और एक एकीकृत रसद समर्थन **(ILS)** पैकेज शामिल है।
- ब्रह्मोस के सौदे की परिकल्पना **2017** में की गई थी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने **2020** में सेना की "क्षितिज **2** प्राथमिकता परियोजनाओं" में इसे शामिल करने की मंजूरी दी थी।

मैरीटाइम थिएटर कमांड

- भारतीय नौसेना ने हाल ही में मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है।
- बैठक में इसके गठन को लेकर भारतीय सेना और वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता वाइस एडमिरल अजयेंद्र बहादुर सिंह, कमांडर और पश्चिमी नौसेना ने की।
- गौरतलब है कि भारतीय सेना की ओर से सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके डिमरी को साउथ-वेस्ट आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर के साथ मिलकर इस कमांड के गठन का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है.
- भारत में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा।
- युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए थिएटर कमांड बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, सेना के लिए एक थिएटर कमांड, जिसका नेतृत्व सेना का एक सैनिक करता है, और वायु सेना-नौसेना इस कमांड के सहयोगी के रूप में कार्य करती है।
- इसी तरह, एक मैरीटाइम थिएटर कमांड में, नौसेना युद्ध की मुख्य नेता होगी और सेना और वायु सेना द्वारा समर्थित होगी।
- एक निश्चित थिएटर कमांड बनाने का फायदा यह है कि यहां से बनाई गई रणनीतियां दुश्मन पर सटीक प्रहार करना आसान बनाती हैं। इस समय देश में करीब **15** लाख सशस्त्र बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत होती है।

Yojna IAS

- माना जा रहा है कि एबी सिंह नौसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्हें मैरीटाइम थिएटर कमांड की जिम्मेदारी मिलेगी|

Swadeep Kumar

Yojna IAS